आंध्र प्रदेश सरकार

बनाम

जी वेंकट रत्नम

(2008 की सिविल अपील संख्या 4582)

जुलाई 21. 2008

(तरुण चटर्जी और आफताब आलम, जे.जे.)

सेवा कानून:

स्थानांतरण-आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया - यह माना कि: स्थानांतरण का आदेश न तो किसी वैधानिक नियमों का उल्लंघन है और न ही इसे दुर्भावनापूर्ण बताया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से सद्भावना की कमी के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से निराधार और अस्थिर है - स्थानांतरण के मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

न्यायिक संयम:

उच्च न्यायालय- सरकारी अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करने वाले एक कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए- माना: उच्च न्यायालय द्वारा फैसले में सरकारी अधिकारियों के बारे में की गई अत्यधिक तीखी टिप्पणियाँ पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होती हैं।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 4582

डब्ल्यू.पी.क्रमांक 2886/2006 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के दिनांक 23.2.2007 के अंतिम निर्णय से।

अपीलकर्ता की ओर से ए. फातिमा (श्रीमती डी. भारती रेड्डी के लिए)।

प्रतिवादी की ओर से जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बायरापानेनी और सिद्धार्थ पटनायक।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

स्वीकृति दी गई।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

प्रतिवादी पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार में तकनीकी सहायक हैं । उन्हें निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय, हैदराबाद के कार्यालय में तैनात किया गया था, जहां वे वर्ष 1985 में अपनी नियुक्ति के बाद से 20 वर्षों की अवधि तक निर्बाध रूप से रहने में सक्षम थे। 29 जून, 2005 को निदेशक द्वारा जारी एक आदेश द्वारा उन्हें हैदराबाद से स्थानांतरित कर दिया गया और सहायक निदेशक (तकनीकी), पुरातत्व और संग्रहालय, काकीनाडा के कार्यालय में तैनात किया गया। उन्होंने अपने स्थानांतरण आदेश को ओ.ए. नंबर 2005 का 3050 के माध्यम से आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष में चुनौती दी। उस समय विभागीय अधिकारियों के समक्ष उनकी दायर अपील लंबित थी। इसलिए, न्यायाधिकरण ने 4 जुलाई, 2005 के आदेश द्वारा संबंधित विभागीय प्राधिकारी को चार सप्ताह के भीतर अपील का निपटान करने के निर्देश के साथ आवेदन का निपटारा कर दिया। विभागीय अपील अंततः 3 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। प्रतिवादी ने एक बार फिर 2005 के ओ.ए. संख्या 4048 में न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया

लेकिन न्यायाधिकरण ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ओ.ए. को आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 द्वारा खारिज कर दिया।

प्रतिवादी ने 2006 की रिट याचिका संख्या 2886 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और 23 फरवरी, 2007 के फैसले और आदेश द्वारा प्रतिवादी के स्थानांतरण के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश के खिलाफ अपील में आया है।

उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है और हमें यह कहते हुए खेद है कि यह असामान्य और अजीब है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह जाहिर है कि फैसला क्रोध में सुनाया गया था। यह क्रोध सरकारी वकील या निदेशक (उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रतिवादी) के कारण हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने न केवल न्यायिक संतुलन और संयम खो दिया, बल्कि पूरी तरह से निराधार निष्कर्ष पर पहुंच गया। फैसले में विलियम डेलरिम्पल की किताब, द लास्ट मुगल के एक अंश का हवाला दिया गया है कि कैसे दिल्ली में लाल किले को अंग्रेजों ने नष्ट किया गया और कैसे औपनिवेशिक काल की क्षति की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कायम रखा गया है। कोई यह नहीं देख पाता कि लाल किला, जिसके रख-रखाव से आंध्र प्रदेश सरकार का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, वह इस सब में कैसे आ जाता है। लाल किले की दुर्दशा के संदर्भ के बाद यह टिप्पणी आती है कि आंध्र प्रदेश में भी प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल बेहतर स्थिति में नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय यह घोषित करता है कि जिन एजेंसियों और लोगों को देश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित और बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे जिम्मेदारी के निर्वहन में काफी असक्षम और अप्रभावी हैं। लेकिन एक बार फिर हम न्यायालय के समक्ष इस

साधारण मुद्दे की प्रासंगिकता को देखने में विफल रहे। दुर्भाग्य से यह एकमात्र विसंगति नहीं है। निर्णय में, एक से अधिक स्थानों पर, सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्यों के बारे में अत्यधिक तीखी टिप्पणियाँ की गई हैं, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमें पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होती हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय पूरी तरह से प्रतिवादी के बयान जो उसने स्वयं द्वारा कहे गये और उसकी अपनी क्षमता के बारे में उसके लंबे-चौड़े दावों से प्रभावित हो गया है और वस्तुतः उसे अपनी पोस्टिंग की जगह चुनने की अनुमति दे दी है। निर्णय की शुरुआत में प्रतिवादी की योग्यताओं की गणना की गई है जिसमें दो मास्टर डिग्री, एक संस्कृत में और दूसरी पुरातत्व में, एक बी.एड शामिल है। संस्कृत में डिग्री और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से साहित्य शिरोमणि की डिग्री। इसके बाद निर्णय इस प्रकार आगे बढ़ता है:

> "याचिकाकर्ता जैसा कि दलीलों से प्रतीत होता है कि वह एक उच्च योग्य व्यक्ति है। जिस आत्मविश्वास के साथ उसने 13.3.2006 के हलफनामे में इस आशय का दावा किया था कि 'यदि किसी अन्य कर्मचारी के पास मेरा कौशल, ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव है तो मैं अपना काम छोड़ देता हूं।" यह न्यायालय को इस मामले की गहराई से जांच करे और विवादित आदेश को शासन प्रबंध के दौरान मात्र स्थानांतरण के आदेश के रूप में नहीं माने।"

इसमें आगे कहा गया है:-

> "याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे दिनांक 13.3.2006 में दावा किया कि उसे प्राचीन चट्टानों, पत्थरों और ब्राह्मी, प्राचीन तेलुगु, कन्नड़, नागरी, तमिल और तमिल ग्रंथ में अंकित ताम्रपत्र शिलालेख रहस्य

को समझने में विशेषज्ञता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के अलावा पूरे पुरातत्व विभाग में किसी अन्य कर्मचारी के पास इन मामलों में विशेषज्ञता, ज्ञान या अनुभव नहीं है और उनकी सेवाओं की प्रधान कार्यालय में अधिक आवश्यकता है।"

तब न्यायालय स्वयं को यह याद दिलाना चाहता है कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और इसमें हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह विस्तार से बताता है कि यह न्यायिक नीति दो कारणों पर आधारित है, एक तो राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के एक विशेष स्थान पर लंबे समय तक बने रहने से अवांछनीय परिणाम पैदा होने की संभावना होती है जैसे निहित स्वार्थों का उत्तपन्न होना, शक्ति का दुरुपयोग करना जो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य से प्राप्त होती है और दूसरा प्रशासन की अनिवार्यताओं के लिए किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता होती है। फिर यह स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है कि पहला कारण, यानी किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रहने की अवांछनीयता, प्रतिवादी के मामले पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि पुरातत्व में, किसी भी घटना में प्राचीन काल में इतिहास की सूखी हड्डियाँ' पर काम किया जाता था और निपटाया जाता था।

इसके बाद अदालत ने यह माना कि प्रतिवादी का स्थानांतरण भी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण नहीं किया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय ने हैदराबाद और काकीनाडा में रखी विभिन्न भाषाओं में पांडुलिपियों की सूची का उल्लेख किया और याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार किया कि अपने ज्ञान और क्षमता के साथ वह राज्य में किसी भी अन्य स्थान की तुलना में मुख्य कार्यालय हैदराबाद में काम करने के लिए सबसे उपयुक्त है। न्यायालय ने अपने हलफनामे में प्रतिवादी के दावे का उल्लेख किया है कि पूरे पुरातत्व विभाग में इन मामलों में

विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुभव में उनके बराबर कोई अन्य कर्मचारी नहीं है और उनकी सेवाओं की प्रधान कार्यालय में अधिक आवश्यकता है और बताते हैं कि निदेशक द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं था। जो देखा गया, वह इस प्रकार से है:-

> "वह काम की प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से मौन है जो हैदराबाद के राज्य संग्रहालय में ले जाना आवश्यक है और यह भी कि क्या कोई अन्य व्यक्ति है जो उक्त कार्य को करने के लिए योग्य है।"

अंत में, न्यायालय ने पाया कि निदेशक द्वारा किए गए स्थानांतरण के मूल प्रस्ताव में प्रतिवादी की पोस्टिंग का स्थान कुरनूल दिखाया गया था। न्यायालय का मानना है कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रतिवादी को अंततः कुरनूल के स्थान पर काकीनाडा में स्थानांतरित क्यों किया गया। इन सामग्रियों पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी का स्थानांतरण स्पष्ट रूप से, कम से कम कहने के लिए, प्रामाणिक नहीं था।

हम यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दी गई ऐसी कमजोर और काल्पनिक दलीलों पर प्रतिवादी के स्थानांतरण आदेश को सत्यता की कमी बताते हुए फटकार लगाई। हम इस बात से काफी संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार की ओर से मामले में विश्वसनीयता की कमी के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से निराधार और अस्थिर है। स्थानांतरण के मामले में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कानूनी स्थिति इतनी अच्छी तरह से स्थापित है कि उसे यहां दोहराया नहीं जा सकता। प्रतिवादी का स्थानांतरण न तो किसी वैधानिक नियमों का उल्लंघन है और न ही इसे किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण बताया जा सकता है। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार

की जाती है, चुनौती के तहत आने वाले आदेश को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

मामले की सुनवाई के समापन पर प्रतिवादी के वकील ने कहा कि सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया है। यह प्रतिवादी को हैदराबाद वापस लाने को इच्छुक था और इस आशय का आदेश जारी होने की संभावना थी। हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है।'

आर.पी.

स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपिका रामावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।